असहाय स्वरूप का होता है। चुनाव न तो ठीक ढग से और न ही नियमित रूप से किए जाते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं, उन के पास न तो लोगों का विश्वास होता है और न ही वे उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं।"

"चार शताब्दियों के दौरान, राज्यों तथा केन्द्र में केन्द्रीकृत निकायों ने अनेक औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्टिंग पद्धतियों का विकास किया है जो किसी भी प्रकार के कार्यकलापों को शुरू करने से पहले प्रीआडिट स्वरूप की होती है। इस से न केवल विकास की प्रक्रिया पर बाधा उत्पन्न होती है बल्कि अत्यधिक विलंब भी होता है। जिस के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं बनाया जाता। समितियों तथा निवेश बोर्डों और अन्य द्वारा लंबी जांच एवं विलब, स्पष्टीकरण और पद्धति, जो विद्यमान होती हैं, निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का उपहास करती है।"

"यह आशा की गई थी कि देश स्वतंत्र होने के पश्चात् लोगों की सहभागिता की प्रक्रिया जोर पकड़ेगी। समय के साथ-साथ जो कुछ हुआ, वह इस के विपरीत था। लोगों की सहभागिता आज कर्मकांडी है और अधिकांश में सत्ता के लिए राजनीतिक दलों को केवल वोट देने से संबंधित है। ऐसा पांच वर्ष में एक बार होता है। जब तक कि चुनावों की घोषणा पहले नहीं होती। चुनाव करवाने में न केवल अत्यधिक धन व्यय होता है अपितु जाति, विचारधारा, निहित स्वार्थ और धनबल के आधार पर समाज के टुकड़े भी हो जाते हैं। चूंकि राजनीतिक प्रक्रिया का अभी तक ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, इसलिए लोगों की जो आशा है, वह विभिन्न दलों के साथ, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य और प्रयोजन के, ऐसा ही खेल खेलते रहने की है। चुनाव का राजनीतिकरण केवल एक ऐसा साधन बन गया है जिस के द्वारा लोगों में देश की प्रबंध प्रक्रिया में शामिल होने की भावना पैदा होती है। विकास के कार्य में, पंचायत पद्धति की विफलता ने, विद्यमान कानूनों पर आधारित ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर अथवा जिला स्तर की संस्थाओं के निर्माण की आशा के बिना भी, लोगों को असहाय बना दिया है।"

(ग) कार्यदल की रिपोर्ट पर मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्वयं सेवी ऐजेंसियों आदि से गहन परामर्श करने की आवश्यकता है। योजना आयोग, कार्यदल की रिपोर्ट को ऐसे सभी निकायों/व्यक्तियों को भेजने की प्रक्रिया में है। उन से परामर्श करने के बाद समुचित उपाय किए जाएंगे ताकि वे आठवीं योजना में आयोजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को वहन कर सकें।

SS Previously Unstarred Question 4541, transferred from 31st March 1992.

Utilisation Certificates by Darjeeling Gorkha Hill Council

$$4432-C. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that no utilisation certificates were given by the Darjeeling Gorkha Hill Council for the money provided through Central Pool as S.C.A. during the year 1989-90 and 1990-91;

(b) if so, what is the amount involved; and

(c) what action is proposed against such defaults?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) For the Annual Plans 1989-90 and 1990-91 of Darjeeling Gorkha Hill Council, the allocations of S.C.A. were Rs. 18.75 crores and Rs. 21.00 crores respectively. The State Government have till now received utilisation certificate for the S.C.A. allocated during 1989-90.

(c) We expect that utilisation certificates for the S.C.A. released in 1990-91 will be submitted by the Council in due course.

Scheme for Women Entrepreneurs

4433. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3324 given in the Rajya Sabha on 23rd March, 1992 and state:

(a) whether Government propose to inaugurate any new scheme for encouraging women Entrepreneurs for production and export of readymade garments including banians to foreign countries with subsidy and tax remission; and

(b) if so, what are the details of such schemes and by when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No, Sir.